

विद्यार

**पूरी दुनिया में सबसे तेज गति
से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी**

अक्सर कहा जाता है कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या में तेज वृद्धि हो रही है लेकिन अब जो आंकड़े सामने आये हैं वह दर्शा रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी में सबसे तेज वृद्धि हो रही है। आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि अगर यही रुझान जारी रहे तो 2050 तक मुस्लिम और ईसाई आबादी लगभग बराबर हो सकती है और 2070 के बाद मुस्लिम जनसंख्या ईसाइयों से आगे निकल सकती है। यह परिवर्तन न केवल सांख्यिकीय रूप से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी पूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की संख्या 347 मिलियन (34.7 करोड़) बढ़ी जोकि अन्य सभी धर्मों की सम्मिलित वृद्धि से भी अधिक है रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से युवा आबादी और उच्च प्रजनन दर के कारण हुई। रिपोर्ट कहती है कि 2010 में ईसाई वैश्विक आबादी का 30.6 लाख थे, जो 2020 में घटकर 28.8 प्रतिशत रह गए। इस गिरावट का मुख्य कारण था धर्मिक त्याग, जिसमें खासतौर पर लोग पश्चिमी दैशों में ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं। वहीं रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक हिंदू आबादी लगभग 1.2 अरब हो गई है (2010 में 1.1 अरब थी) यानी 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि हिंदुओं का वैश्विक प्रतिशत 15 प्रतिशत से मामूली घटकर 14.9 लाख हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुओं की प्रजनन दर वैश्विक औसत के अनुसूचि है और धर्मांतरण की दर भी बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक दुनिया के 95 लाख हिंदू भारत में रहते हैं। इसके अलावा 'नो-रिलिजन' वर्ग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धर्मिक रूप से असंलग्न लोगों की संख्या 270 मिलियन बढ़कर 1.9 अरब हो गई है और इनका वैश्विक हिस्सा 23.3 लाख से बढ़कर 24.2 लाख हो गया है। वहीं प्रमुख धर्मों में केवल बौद्ध धर्म की आबादी 2010 की तुलना में 2020 में कम रही। 2010 में बौद्ध वैश्विक जनसंख्या का 4.9 लाख थे, पर 2020 में यह घट गया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हिंदुओं की आबादी 2010 के 80 प्रतिशत से घटकर 2020 में 79 प्रतिशत हो गई है। वहीं भारत में मुस्लिम आबादी 2010 के 14.3 लाख से बढ़कर 2020 में 15.2 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि भी मुख्य रूप से प्रजनन दर और युवा जनसंख्या के कारण है, न कि धर्मांतरण से। हालांकि भारत में मुस्लिमों की यह वृद्धि अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश की तुलना में धीमी है, पर फिर भी यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय परिवर्तन है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 में दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी में से 35 लाख मुसलमान 15 वर्ष से कम आयु के थे। उल्लेखनीय है कि इतनी युवा जनसंख्या होने के कारण जन्म दर अधिक बनी रहती है, जिससे आबादी तेजी से बढ़ती है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर अन्य धर्मिक समुदायों की तुलना में अधिक है। इससे मुस्लिम जनसंख्या को प्राकृतिक विकास दर भी अधिक होती है। साथ ही, रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिमों में धर्म छोड़ने वालों की संख्या और अन्य धर्मों से इस्लाम अपनाने वालों की संख्या लगभग बराबर है। यानी धर्मिक स्वचिंग का असर नगण्य है, जिससे शुद्ध जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म के कारण होती है। इसके अलावा, रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1 लाख वयस्क ही अपने जन्मजात धर्म से अलग होकर अन्य धर्म अपनाते हैं, विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान, इन दोनों समुदायों में धर्म-परिवर्तन के दर अत्यंत कम है।

बहरहाल यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आने वाले दशकों में विश्व की धार्मिक जनसंख्या संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने के मिल सकते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी मैं तेज़ वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, ईसाई समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ेंगी, खासकर यूरोप और अमेरिका में। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू समुदाय वैश्विक रूप से स्थिर रहेगा, परंतु भारत के भीतर उसके अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट संभव है। इसमें कोइदो राय नहीं कि यह रिपोर्ट न केवल जनसांख्यिकी विश्लेषण बल्कि नीति-निर्धारण, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बिहार चुनावों में महिलाओं पर दांव के निहितार्थ

बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, नये-नये मुद्दों को उछाला जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड हो या तंत्र मंत्र के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को जला देने की त्रासद घटना—नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर सौदैह के सवालों के साथ मुख्य विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तथा है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएँ कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहाँ अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे। यह अंकड़ा दिखाता है कि चुनावी जीत में महिला मतदाता की निर्णायक हो सकते हैं, साफ है सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आग्रहों से अधिक लौंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पंचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। चुनावों की दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किरदार निभाने के कारण ही हरेक राजनीतिक दल महिला वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस-वाम दलों का महागठबंधन 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दंबं को समझा जा सकता है। जातिगत और स्थानीय समीकरण भुनाने के लिए निश्चित ही यह एक संगठित चाल है, जहां जाति और आवासीयता



के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। हाल ही में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यह देखा गया कि देश के विभिन्न प्रदेशों की योग्य लड़कियां इटरव्यू देने आईं, जिनमें से अनेक ने सफलता प्राप्त की और अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रही हैं। निस्संदेह, यह एक संदर्भांतिक रूप से प्रगतिशील और समावेशी समाज का प्रतीक है, जहाँ महिलाएं सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें, तो महिला सुरक्षा, सामाजिक असमानता, आवास व परिवारिक बाधाएं, और प्रवास की मजबूरियाँ अब

भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि सरकारें योग्य महिलाओं को उनके घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो यह न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थिरता और पारिवारिक सहूलियत का भी कारण बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पिक टॉयलेट, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे कई कदम इस सिलसिले में पहले ही

उठाए जा चुके हैं। यह मान्यता कि बेटियां अब सिर्फ अपने घरों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार हैं, नीति निर्माण में स्पष्ट झलकने लगा है। यह न केवल बिहार की महिलाओं को उनके अधिकार का अनुभव कराएगा, बल्कि बेरोजगारी से जूझते प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा के पलायन को भी रोकेगा। इस फैसले से खास तौर पर निम्न और मध्यमवर्गीय महिलाओं को फायदा होगा, जिनके लिए दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करना एक बड़ा परिवारिक और सामाजिक संकट बन जाता है। घर के पास नौकरी मिलने से न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थायी उपरिस्थिति और भविका भी मजबूत होगी।

स्पाया उपर्याका और नूज़ूना भा न ज़ज़ूना हाना।
हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे नीतीश कुमार की चुनावी चाल बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, बल्कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उछालकर बोट बटोरने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि महिला आरक्षण सही है, लेकिन रोजगार के अवसर कब हैं? सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्षों से लटकी रहती है, परीक्षा की तारीखें टलती हैं, नियुक्ति पत्र देर से आते हैं, ऐसे में आरक्षण का लाभ कब और किसे मिलेगा? उनकी बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आरक्षण की नीति।

नात।
यह महिला आरक्षण अब केवल बिहार के स्थायी निवासियों अर्थात् डोमिसाइल महिलाओं के लिए ही होगा। यानी जो महिलाएं राज्य की स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा-उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੀ ਰਾਯ: ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਸੇ ਲਿਗਡ ਰਹੀ ਕਾਨੂਨ-ਤਾਵਦਿਆ

ડૉ. આરીષ વર્ણાસ્થ

पंजाब में तेजी से बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महाराष्ट्र में उद्धव और राजठाकरे का गठबंधन और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर इस हते पंजाबी अखबारों ने अपनी राय प्रमुखता से रखी है। सूबे की कानून व्यवस्था पर चंडीगढ़ से प्रकाशित पंजाबी ट्रियून अपने संपादकीय पंजाब में बढ़ता अपराध में लिखता है- अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की दिनदहाड़े हत्या और मोगा के एक लीनिक में अभिनेत्री तानिया के पिता की गोली मारकर हत्या ने एक तरह से यह उआगर कर दिया है कि किस तरह संगठित अपराध राज्य में आपराधिक गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे रहा है। अखबार लिखता है शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी, नशे की लत व जल्दी पैसे कमाने का लालच कई पंजाबी युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है।



सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और गैंगस्टरों का महिमांडन आग में घी डालने का काम कर रहा है। पंजाब में आपराधिक-आतंकवादी गठजोड़ अब स्थानीय नहीं रहा; यह अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी रूप से सक्षम और वैचारिक रूप से अस्थिर हो गया है। यह संकट जितना लंबा चलेगा, पंजाब के भविष्य को पटरी पर लाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा।

जालंधर से प्रकाशित %पंजाबी जागरण% लिखता है-
 पंजाब पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के कारण सुखियों में है। अबोहर में हुई एक घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। लारेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक समह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। ऐसा नहीं है कि राज्य में इस तरह की यह पहली घटना है। यह घटना आम बात है। अबोहर की घटना ने पंजाब में जबरन बसलू के बढ़ते मामलों पर भी प्रकाश डाला है।

जालधर से प्रकाशत अजात लिखता है- आजकल पूरे राज्य में लूटपाट का बोलबाला है। अबोहर की घटना के बाद सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है।

विपक्ष खासकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष बहस की मांग की है। जालंधर से प्रकाशित रोजाना पंजाब टाइम्स लिखता है— वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में जबरन वसूली और धमकियों से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई है। पंजाब पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 से फरवरी 2023 तक जबरन वसूली

और धमकी के 278 मामले दर्ज किए गए, जो मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक बढ़कर 307 हो गए। यह वृद्धि समाज और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। अखबार लिखता है, सिद्धू मुसेवाला की हत्या ने संगठित अपराध की गंभीरता को उत्तापित किया, लेकिन इसके खलिफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जबरन वसूली की घटनाओं ने पंजाब के व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। कई व्यापारी और कलाकार धमकियों के कारण अपना व्यवसाय या पेशा छोड़ने की सोच रहे हैं। इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

चंडीगढ़ से प्रकाशित रोजाना स्पोक्समैन लिखता है, इस साल अब तक चंडीगढ़ में हत्या के 15 मामले दर्ज किए गए

हैं। आंकड़े बताते हैं कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, अन्य कारकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब और चंडीगढ़ की ओर युवा पीढ़ी के बढ़ते पलायन के कारण भी गंभीर और घातक अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जिन व्यवसायों में स्थानीय लोगों की विशेषज्ञता है, उनमें बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसी मार्गें राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उठने लगी हैं। पंजाब और चंडीगढ़ को भी अब इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों पर चंडीगढ़ से प्रकाशित %पंजाबी ट्रिब्यून% लिखता है- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही उसने चुनाव आयोग से एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है- अभी क्यों? अदालत ने यह बिल्कुल सही बात कही है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की कवायद से लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्वर्य व्यक्त किया है कि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। उसका मानना है कि चुनाव अधिकारियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करना चाहिए। चंडीगढ़ से प्रकाशित %देशसेवक% लिखता है- छोटी-मोटी बाधाओं के बावजूद, चुनाव आयोग ने न केवल देश में, बल्कि दुनिया में भी समान अर्जित किया है। बिहार चुनावों में चुनाव आयोग के सामने अपनी ईमानदारी बचाने की चुनौती है।

जालधर स प्रकाशत अज दा आवज लिखता ह- बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रखे हैं। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। रसूखदारों और कारोबारियों की हत्याओं की घटनाओं ने राज्य सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। युवा बेरोजगार हैं और आम जनता महांगई की मार झेल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी अन्य राजनेताओं की तरह चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। अखबार आगे लिखता है, बिहार सरकार द्वारा कल्पणाकारी योजनाओं की शुरुआत के लिए चुना गया समय उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा है। अगर सरकार वाकई लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर और सजग होती, तो ये घोषणाएं एक-दो साल पहले ही की जा सकती थीं। यह तो समय ही बताएगा कि सरकार के अंतिम दिनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई घोषणाएं कारण साबित होती हीं या नहीं।

महाराष्ट्र में उद्घव और राज ठाकरे के गठबंधन पर जालंधर से प्रकाशित %अज दी आवाज% लिखता है- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने के फैसले ने दोनों चर्चेरे भाइयों, उद्घव ठाकरे और राज ठाकरे को करीब आने का अवसर दिया। ऐसा लगता है मानो दोनों नेता साथ आने के मौके का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल, ये दोनों पार्टीयां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठाकरे भाइयों का तात्कालिक लक्ष्य प्रतिष्ठित मुंबई नगर निगम में पैर जमाना है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी एमवीए दोनों ही आंतरिक मतभेदों से घिरे हुए हैं। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर, आगामी समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक उत्तर-चढ़ाव देखने को मिलेंगे और उनका प्रदर्शन राजनीति में उनका भविष्य भी तय करेगा। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेंगे या एमवीए के सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे।

यद्युगु के प्रकाराता %मजाजा ट्रिप्पल 10% लेखा ह-
शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्घव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा हताशा में अपनाया गया यह अंतिम उपाय है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्घव और भतीजे राज ठाकरे अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने के लिए %मराठी मानुष% कार्ड पर भरोसा कर रहे हैं। वे भाजपा पर किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र के लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं; हालांकि, उनकी लडाई केवल भगवा पार्टी के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली %आधिकारिक% शिवसेना के खिलाफ भी है। ठाकरे बंधुओं के पुनर्निर्मलन का मतलब है कि शिंदे अब मराठी वोट को हल्के में नहीं ले सकते।

